

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 872]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 नवम्बर 2025 — कार्तिक 27, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 नवम्बर 2025

क्र. 6798/डी. 163/21-अ/प्रारू./छ.ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 04-09-2023 को राज्यपाल एवं दिनांक 06-11-2025 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 33 सन् 2025)

## भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2023.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाये। छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम 1899 का सं. 2) का संशोधन.
3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन.

(एक) खण्ड (11) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(11-क) “ई-स्टाम्प अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प” से अभिप्रेत है, स्टाम्प शुल्क के भुगतान को निर्दिष्ट करने के लिए सृजित कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजीटल रिकार्ड अथवा कागज पर उसकी छाप;”

(दो) खण्ड (12) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(12-क) “परिबद्ध” से अभिप्रेत है, लिखत को, इस संदर्भ में उस पर किए गए पृष्ठांकन के साथ, लोक अधिकारी की अभिरक्षा में लेना;”

(तीन) खण्ड (16—क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(16—ख) “बाजार मूल्य” से किसी ऐसी सम्पत्ति, जो किसी लिखत की विषयवस्तु है, के संबंध में अभिप्रेत है, वह मूल्य, जो इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित रीति में इस हेतु सशक्त प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया गया हो, जो ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख को, यदि खुले बाजार में विक्रय किया जाता, तो उस संपत्ति के लिए प्राप्त हुई होती या प्राप्त होगी, अथवा प्रतिफल, जो लिखत में उपदर्शित हो, जो भी लागू हो;

“(16—ग) “बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत” से अभिप्रेत है, राज्य में विभिन्न ग्रामों, निवेश क्षेत्रों, नगरपालिकाओं, निगमों एवं पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्रों में संपत्ति से संबंधित लिखत पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के बाजार मूल्यों की सूची;”

(चार) खण्ड (26) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(26) “स्टाम्प” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अन्तर्गत शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजन हेतु, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी ऐजेंसी या व्यक्ति द्वारा कोई चिन्ह, मुद्रा या पृष्ठांकन और इसमें आसंजक अथवा छापित मुद्रा अथवा ई—स्टाम्प या डिजीटल रूप से सृजित स्टाम्प सम्मिलित है।”

## 4. मूल अधिनियम की धारा 35 के परन्तुक में,—

धारा 35 का  
संशोधन.

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(क) कोई ऐसी लिखत, उस शुल्क के, जिससे कि वह प्रभार्य है अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम के साथ—साथ स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिए प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से, 2% शास्ति का भुगतान कर दिये जाने पर, साक्ष्य में ग्राह्य होगी :

परन्तु किसी भी मामले में, इस प्रकार संगणित की गई शास्ति की राशि, वसूल किए जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी;”

(दो) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(घ) इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अध्याय 9 या अध्याय 10 के भाग—घ के अधीन की कार्यवाही से भिन्न दाण्डिक न्यायालय की किसी कार्यवाही में किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण किए जाने से निवारित नहीं करेगी।;”

## 5. मूल अधिनियम की धारा 40 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

धारा 40 का  
संशोधन.

“(ख) यदि, जांच करने के पश्चात, उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत, शुल्क से प्रभार्य है और वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम

के साथ स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिए प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से, 2% शास्ति का भुगतान किया जाये तथा उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है। यह रकम उस व्यक्ति द्वारा देय होगी, जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो :

परन्तु किसी भी मामले में, इस प्रकार संगणित की गई शास्ति की राशि, वसूल किए जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जब ऐसी लिखत, केवल इस कारण से परिबद्ध की गई है कि वह धारा 13 या 14 के उल्लंघन में लिखी गई है, तब कलेक्टर, यदि वह ठीक समझे, इस धारा द्वारा विहित की गई पूरी शास्ति से छूट दे सकेगा।”

6. मूल अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) का लोप किया जाये।

धारा 45 का  
संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 47—क में,—

धारा 47—क का  
संशोधन.

(एक) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर, कलेक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, जांच करने के पश्चात्, उस संपत्ति के, जो कि ऐसे लिखत की विषय-वस्तु है, बाजार मूल्य का तथा यथापूर्वोक्त शुल्क का अवधारण करेगा।

यदि ऐसी लिखत, सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क

को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम के साथ-साथ स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिए प्रतिमाह अथवा उसके भाग के लिए, लिखत के निष्पादन की तारीख से, 2% शास्ति का भुगतान किया जाये। यह रकम उस व्यक्ति द्वारा देय होगी, जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी हो :

परन्तु किसी भी मामले में, इस प्रकार संगणित की गई शास्ति की राशि, वसूल किये जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी।”

(दो) उप-धारा (3) में, शब्द “यथापूर्वोक्त शुल्क का अवधारण” के स्थान पर, शब्द “यथापूर्वोक्त शुल्क के साथ साथ शास्ति का अवधारण” प्रतिस्थापित किया जाये।

(तीन) उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(4) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन कलेक्टर के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, विहित रीति में, संभाग के आयुक्त को अथवा राज्य शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी को, कर सकेगा :

परन्तु कोई भी अपील, तब तक ग्राह्य नहीं की जायेगी, जब तक कि ऐसा व्यक्ति, कलेक्टर द्वारा आदेशित कम स्टाम्प शुल्क की राशि का कम से कम 25% जमा नहीं कर देता। ऐसी राशि, अपीलीय अधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार देय राशि के विरुद्ध समायोज्य अथवा वापसी योग्य होगी।”

8. मूल अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (4) के द्वितीय परन्तुक में,—

धारा 56 का  
संशोधन.

(एक) खण्ड (दो) में, पूर्ण विराम चिन्ह “।” के स्थान पर,  
अर्धविराम चिन्ह “;” प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये,

अर्थात्:—

“(तीन) तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक कि वसूली राशि के 25% राशि का संदाय किये जाने का समाधानप्रद साक्ष्य उसके साथ नहीं लगा हुआ हो। ऐसी राशि, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार देय राशि के विरुद्ध समायोज्य अथवा वापसी योग्य होगी।”

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 नवम्बर 2025

क्र. 6798/डी. 163/21-अ/प्रारू./छ.ग./25. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2023 (क्रमांक 33 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल सिन्हा, उप-सचिव.

# CHHATTISGARH ACT

(No. 33 of 2025)

## THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2023.

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Act, 2023.

**Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh be amended in the manner hereinafter provided.

**Amendment of Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Chhattisgarh.**

3. In Section 2 of the Principal Act,-

**Amendment of Section 2.**

(i) after clause (11), the following clause shall be inserted, namely:-

“(11-A) “e-stamp or electronic stamp” means any electronic or digital record created or its impression on paper to denote the payment of stamp duty;”

- (ii) after clause (12), the following clause shall be inserted, namely:-

"(12-A) **"Impound"** means to take an instrument into custody of the Public Officer with an endorsement made thereon in this context;"

- (iii) after clause (16-A), the following clause shall be inserted, namely:-

"(16-B) **"Market Value"** in relation to any property which is the subject matter of an instrument, means the price which such property would fetch or would have fetched if sold in the open market, on the date of execution of such instrument determined by the Authority empowered to do so in the manner laid down under this Act or the rules made there under or the consideration stated in the instrument, whichever is applicable;

(16-C) **"Market Value Guidelines"** means the set of market values of immovable property in various villages, planning areas, municipalities, corporations and other areas notified in the State by the

designated authority under the rules framed under this Act for the purpose of determining the chargeability of stamp duty on an instrument related to the property;"

- (iv) for clause (26), the following clause shall be substituted, namely:-

"(26) **"Stamp"** means any mark, seal or endorsement by any agency or person duly authorized by the State Government and includes an adhesive or impressed stamp, e-stamp or digitally generated stamp, for the purpose of duty chargeable under this Act."

**4. In proviso of Section 35 of the Principal Act,-**

**Amendment of  
Section 35.**

- (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) any such instrument shall be admissible in evidence, on payment of the duty with which the same is chargeable or in the case of an instrument insufficiently stamped of the amount required to make up such duty together with a penalty of 2% of the deficient portion of stamp duty for every month or part thereof,

from the date of execution of the instrument:

Provided that in no case the amount of penalty so calculated shall exceed the principal amount of the deficit stamp duty to be recovered;"

(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

"(d) nothing herein contained shall prevent the admission of any instrument in evidence in any proceeding in a Criminal Court, other than a proceeding under Chapter IX or part D of Chapter X of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974);"

5. For clause (b) of sub-section (1) of Section 40 of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely:-

**Amendment of  
Section 40.**

"(b) if, after holding an enquiry, he is of opinion that such instrument is chargeable with duty and is not duly stamped, he shall require the payment of the proper duty or the amount

required to make up the same, together with a penalty of 2% of the deficient portion of stamp duty for every month or part thereof from the date of execution of the instrument and shall certify by endorsement thereon that it is duly stamped. The amount shall be payable by the person liable to pay the duty:

Provided that in no case the amount of penalty so calculated shall exceed the principal amount of deficit stamp duty to be recovered:

Provided further that, when such instrument has been impounded only because it has been written in contravention of Section 13 or 14, the Collector may, if he thinks fit, remit the whole penalty prescribed by this Section;"

6. Sub-section (1) of Section 45 of the Principal Act shall be omitted.

**Amendment of  
Section 45.**

7. In Section 47-A of the Principal Act,-

**Amendment of  
Section 47-A.**

(i) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) On receipt of a reference under sub-section (1), the Collector shall after giving the parties

a reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in such a manner as may be prescribed, determine the market value of the property which is the subject matter of such instrument and the duty as aforesaid.

If such instrument is not duly stamped, he shall require the amount required to make up the appropriate duty, together with a penalty of 2% of the deficient portion of stamp duty for every month or part thereof from the date of execution of the instrument. The amount shall be payable by the person liable to pay the duty:

Provided that in no case the amount of penalty so calculated shall exceed the principal amount of deficit stamp duty to be recovered."

- (ii) In sub-section (3), for the words "duty as aforesaid", the words "duty with penalty as aforesaid" shall be substituted.

(iii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(4) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) or (3) may, appeal in the prescribed manner against such order to the Commissioner of the Division or Officer so appointed by the State Government, by notification in the Official Gazette:

Provided that no appeal shall be entertained unless such person deposits not less than 25% of the deficit amount of stamp duty ordered by the Collector. Such amount shall be adjustable against the amount due or refundable as per the final order of the Appellate Authority."

8. In second proviso of sub-section (4) of Section 56 of the Principal Act,-

**Amendment of  
Section 56.**

(i) in clause (ii), for the punctuation full stop “.”, the punctuation semi colon “;” shall be substituted.

(ii) after clause (ii), the following clause shall be added,  
namely:-

"(iii) entertained unless it is accompanied by  
satisfactory evidence of payment of  
25 % of the amount recovered. Such amount  
shall be adjustable against the amount due or  
refundable as per the final order of the Chief  
Controlling Revenue Authority."